21 आधार सेवा केंद्र काम कर रहे हैं देश भर में भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआइडीएआइ) के। सरकार इसकी संख्या बढ़ाकर 114 करना चाहती है। यह जानकारी यूआइडीएआइ ने गुरुवार को दी है।

www.jagran.com राष्ट्रीय संस्करण
दैनिक जागरण
शुक्रवार 22 नवंबर 2019

कश्मीर में आतंकियों से जुड़ी छह संपत्तियों पर ईडी ने लिया कब्जा

नई दिल्ली, प्रेट्र : कश्मीर में कथित आतंकियों से जुड़ी छह भू-संपत्तियों पर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने कब्जा ले लिया है। वैश्विक स्तर पर प्रतिबंधित पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन के प्रमुख सैयद सलाहुद्दीन के खिलाफ आतंकी फंडिंग से जुड़े मामले में ईडी ने यह कार्रवाई की है।

प्रिवेंशन ऑफ मनी लांड्रिंग एक्ट (पीएमएलए) के तहत ईडी ने इस साल मार्च में ऐसी 13 संपत्तियों को जब्त किया था। इस कानून के तहत सक्षम प्राधिकारी ने हाल ही में उक्त आदेश को बरकरार रखा था जिसके बाद कब्जे का नोटिस जारी किया गया। ईडी के मुताबिक, ये संपत्तियां अनंतनाग, बांदीपोरा और बारामुला जिलों में स्थित हैं और हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकियों मुहम्मद शफी शाह, तालिब लाली, गुलाम नबी खान, जफर हुसैन भट, अब्दुल मजीद सोफी, नजीर अहमद डार व मंजूर अहमद डार के नाम पर हैं। जब्त की गईं सभी 13 संपत्तियों की कुल कीमत 1.22 करोड़ रुपये है। ईडी अधिकारियों के मुताबिक बाकी संपत्तियों पर भी जल्द ही कब्जा ले लिया जाएगा।

केसर क्रांति में बदलेगी कश्मीर के किसानों की किस्मत

रजिया नूर, श्रीनगर

कश्मीर की शान हैं बर्फ से लदी खूबसूरत वादियां और लाल केसर की महकती क्यारियां। केंद्र सरकार केसर क्रांति के बूते कश्मीर के किसानों की किस्मत बदलने में जुटी है। साथ ही सैफरॉन मिशन के बूते अगले कुछ वर्षों में केसर का उत्पादन दोगुना करने का लक्ष्य है। इसका असर भी दिखा और इस बार पिछले दस वर्षों का रिकॉर्ड टूटने की उम्मीद जगाई जा रही थी पर मौसम ने झटका दे दिया है। नवंबर माह के आरंभ में हुई बर्फबारी ने केसर की फसल को खासा नुकसान पहुंचाया।

कश्मीर का केसर दुनिया में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। इसकी वजह से भारत केसर उत्पादन में ईरान के बाद दुनिया में दूसरे स्थान पर है। बाजार में केसर की कीमत डेढ़ से तीन लाख रुपये प्रति किलो है। आतंकवाद प्रभावित इस क्षेत्र में केंद्र सरकार केसर के बूते किसानों का बेहतर भविष्य बनाने में जुटी है। प्रधानमंत्री के आह्वान के बाद स्पाइसेज बोर्ड ने जम्मू कश्मीर सरकार के साथ मिलकर केसर निर्यात एवं विकास एजेंसी का गठन किया और राज्य का बागवानी विभाग भी सक्रिय हुआ।

सब मौसम पर निर्भर

केसर उत्पादक एसोसिएशन के अध्यक्ष अब्दुल मजीद वानी ने कहा कि समय पर बारिश होना मतलब केसर की अच्छी पैदावार। इस साल भी अच्छी फसल होने की उम्मीद थी लेकिन बफर्बारी ने उम्मीदों पर पानी फेर दिया। वानी ने कहा, अगर केसर के खेतों में बोर वेल लगाए जाएं तो हम अगस्त से ही खेती शुरू कर दें और अक्टूबर तक पैदावार समेट लें।

सूक्ष्म सिंचाई फायदेमंद

शेर-ए-कश्मीर कृषि विश्विवद्यालय के प्लांट पैथालोजी विभाग के विज्ञानी अरशद अहमद टॉक ने कहा कि कई वर्षों में समय पर बारिश न होने के चलते केसर के उत्पादन को काफी धक्का पहुंचा था। उन्होंने कहा कि सूक्ष्म सिंचाई से किसानों को केसर की मोड़ा जा सकता है।

कश्मीर में नवंबर में हुई बर्फबारी ने केसर की फसल को खासा नुकसान पहुंचाया है। जागरण

दक्षिण व मध्य कश्मीर में होती है काश्त

केसर की काश्त दक्षिणी कश्मीर के पुलवामा और मध्य कश्मीर के बड़गाम में अधिक की जाती है। घाटी में 3700 हेक्टेयर जमीन (3650 हेक्टेयर पुलवामा तथा बड़गाम जिले में 50 हेक्टेयर जमीन पर केसर की खेती शुरू की गई) और इसमें से 95 फीसद (23 टन) केसर पुलवामा में उत्पादन होता था। पुलवामा में केसर उत्पादन प्रति हेक्टेयर पांच किलोग्राम के आसपास रहा है। वहीं श्रीनगर में यह दो किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है। कश्मीर में करीब 32 हजार किसान केसर की खेती से जुड़े हैं।

मिशन केसर की चुनौतियां मौसम की बाधा : केसर के फूलों का संचय अक्टूबर-नवंबर माह में होता है और पिछले कुछ वर्षों से नवंबर माह के पहले सप्ताह में बर्फबारी हो जाती है। इससे उत्पादन प्रभावित हो रहा है। किसान अगर अगस्त माह में इसका रोपाई का कार्य कर लें तो अक्टूबर माह में फूल ले सकते हैं और ऐसे में बर्फबारी से पहले अपनी फसल ले पाएंगे। पर केसर की खेती ढलान वाले क्षेत्रों में होती है और वहां पानी ठहरता नहीं। ऐसे में बारिश के बाद किसान खेती शुरू करते हैं। प्रशासन टपका प्रणाली से सिंचाई को प्रोत्साहित कर रहा है।

घटता रकबा : 20 वर्षों में केसर के उत्पादन में कुछ कमी आई है। करीब 3700 हेक्टेयर से अधिक भूमि के लिए केसर मिशन शुरू किया गया था, लेकिन बाद में यह दायरा सिकुड़कर 2700 हेक्टेयर तक जा पहुंचा। हालांकि एक समय में यह रकबा पांच हजार हेक्टेयर के करीब पहुंच गया पर उत्पादन गिरने पर बहुत से किसानों ने इससे किनारा कर लिया। पहले वर्ष 2014 के सैलाब ने तबाही मचा दी। सैलाब ने सैफरान बड (कश्मीरी में कोंग मोंड) 60 फीसद तक नष्ट कर दी। सेफरान बड से 8-10 वर्षों तक केसर के फूल लिए जा सकते हैं। दो वर्षों में मौसम थोड़ा अनुकूल रहा और वक्त पर बारिश भी हुई और इससे पैदावार में फिर बढ़ोतरी की उम्मीद पैदा हो गई।

अल्ताफ हुसैन के शरण मांगने पर भारत चुप

नई दिल्ली, जागरण ब्यूरो : लंदन में निर्वासित जिंदगी बीता रहे पाकिस्तानी नेता अल्ताफ हुसैन ने भारत में शरण मांगने की पेशकश की है, लेकिन भारत का रवैया फिलहाल बहुत सकारात्मक नहीं है। इसकी एक वजह यह है कि भारत विश्व बिरादरी को यह संदेश नहीं देना चाहता कि वह पाकिस्तान सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद करने वाले नेताओं को बढ़ावा दे रहा है। दूसरी वजह यह है कि हुसैन की छवि काफी चर्चा में रही है। हालांकि अभी यह भी स्पष्ट नहीं है कि मुहाजिर कौमी मूवमेंट (एमक्यूएम) के नेता हुसैन ने आधिकारिक तौर पर शरण मांगी है अथवा नहीं।

इस बारे में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार से जब पूछा गया तो उन्हें बेहद ठंडी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि इस बारे में गृह मंत्रालय ही बेहतर तरीके से बता सकेगा। दूसरी तरफ, गृह मंत्रालय अल्ताफ हुसैन को लेकर एकदम चुप्पी साधे हुए। हुसैन ने पिछले दिनों एक भारतीय टीवी चैनल को दिए इंटरव्यू में कहा था कि वह भारत में शरण लेना चाहते हैं और इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आग्रह करते हैं। उन्होंने अपनी तरफ से यह भी कहा था कि अगर वह भारत में आते हैं तो यहां राजनीति से दूर रहेंगे।

धोखाधड़ी रोकने के नए तरीके खोजें ऑडिटर

बोले पीएम ▶ देश को पांच लाख करोड़ डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने की दिशा में ऑडिटर्स की अहम भूमिका

कैग को केवल कमियां खोजने वाले ऑडिटर की तरह नहीं, थिंक टैंक की तरह सोचने का सुझाव

नई दिल्ली, प्रेट्र : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को ऑडिटर्स से धोखाधड़ी पर लगाम लगाने और सरकारी विभागों की दक्षता बढ़ाने के नए तौर-तरीके खोजने की अपील की। नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (कैग) के एक सम्मेलन को संबोधित करते हुए मोदी ने देश को पांच लाख करोड़ डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने की दिशा में ऑडिटर्स से भूमिका निभाने को कहा।

प्रधानमंत्री ने कहा, 'हमें धोखाधड़ी को चुनौती देनी होगी। आंतरिक एवं बाहरी दोनों स्तर पर कार्यरत ऑडिटर्स को धोखाधड़ी पकड़ने के नए तौर-तरीके खोजने चाहिए।' मोदी ने कहा कि पिछले पांच साल में धोखाधड़ी पर लगाम लगाने की दिशा में कई कदम उठाए गए हैं। प्रमाणों पर आधारित नीति निर्माण को प्रशासन का हिस्सा बनाने पर जोर देते हुए उन्होंने कहा कि ऑडिटर्स को तकनीक का प्रयोग करना चाहिए। इससे संस्थानों में धोखाधड़ी के मामले पकड़ना आसान होगा।

नई दिल्ली में गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महालेखाकार (अकाउंट्स जनरल) और उप महालेखाकार संगोष्ठी को संबोधित किया। प्रेट्र

2016 के बाद दूसरी बार कैग के सम्मेलन को संबोधित करते हुए पीएम ने कहा, 'देश पांच लाख करोड़ डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में बढ़ रहा है। इसमें आपकी (आडिटर्स की) बड़ी भूमिका है। आप जो भी करेंगे, उससे हमारे नीति निर्माण, दक्षता, निर्णय प्रक्रिया, कारोबार, निवेश, कारोबारी सुगमता एवं अन्य पहलुओं पर सीधा प्रभाव पड़ेगा।' मोदी ने कैग को केवल गलतियां पकड़ने वाले ऑडिटर की तरह नहीं, थिंक टैंक की तरह सोचने को कहा। मोदी ने कहा, 'कैग कई अंतरराष्ट्रीय संस्थानों का ऑडिट करती है और अन्य देशों को भी तकनीकी सहायता मुहैया कराती है। इसलिए आप ऐसी संस्थागत व्यवस्था तैयार कर सकते हैं जिससे ऐसी कंपनियों का ऑडिट करने वाली टीम उन देशों व संस्थानों से जुड़े अपने अनुभव साझा कर सकें।' इससे पहले मोदी ने कैग परिसर में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण भी किया।

हैकाथन आयोजित करे कैग

प्रधानमंत्री ने दक्षता एवं पारदर्शिता बढ़ाने तथा विभिन्न चुनौतियों का तकनीकी समाधान पाने के लिए कैग को हैकाथन आयोजित करने का सुझाव भी दिया। हैकाथन के जरिये देशभर में टेक्नोलॉजी सेक्टर से जुड़े युवा समस्याओं का डिजिटल समाधान मुहैया कराने में मदद कर सकेंगे। मोदी ने कैग को विभिन्न देशों की सर्वश्रेष्ठ तकनीकों अपनाने और भारत में उन पर काम करने को भी कहा। मोदी ने कहा, 'कैग को सिर्फ आंकड़ों तक सीमित नहीं रहते हुए अच्छे प्रशासन (गुड गवर्नेंस) का उत्प्रेरक बनना होगा। आप कैग को कैग प्लस बनाने की दिशा में प्रयासरत हैं और इससे देश को भी लाभ हुआ है।'

बंगाल में गाय चोर के संदेह में पीट-पीटकर दो की हत्या

जागरण संवाददाता, कोलकाता : सरकारी सख्ती के बावजूद बंगाल में मॉब लिंचिंग की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं। ताजा मामला कूचबिहार जिले का है। यहां गाय चोरी के संदेह में दो लोगों की पीट-पीटकर हत्या कर दी गई है। घटना गुरुवार सुबह की है। मृतकों की पहचान प्रकाश दास और बाबला मित्र के रूप में हुई है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार दोनों सुबह पिकअप वैन से गाय लेकर जा रहे थे। कूचबिहार में फुलेश्वरी के पास उन्हें कुछ लोगों ने रोक दिया और पूछताछ करने लगे। इसके बाद वे लोग उन्हें गाय चोर बताकर मारने-पीटने लगे। सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों को हमलावर भीड़ से छुड़ाकर साथ ले गई। दोनों घायलों को कूचबिहार जिला अस्पताल में ले जाया गया, जहां जांच के बाद चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।

मृतकों के परिवारों ने हमलावरों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने की मांग की है। प्रारंभिक जांच में पता चला है कि दोनों को गाय चोर समझकर हमला किया गया। गंभीर चोट लगने के कारण दोनों की मौत हुई है। आरोपितों के विरुद्ध संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है।

सेवानिवृत्ति आयु बढ़े तो जज और काम करना चाहेंगे : सीजेआइ

- चीफ जस्टिस बोबडे ने कहा-अटॉर्नी जनरल की राय से हूं सहमत
- वेणुगोपाल की सीजेआइ का कार्यकाल तीन साल करने की दलील

नई दिल्ली, प्रेट्र : उच्च न्यायालयों के जजों की सेवानिवृत्ति की आयु बढ़ाने पर चर्चा के बीच देश के नए मुख्य न्यायाधीश शरद अरविंद बोबडे ने कहा है कि अगर सेवानिवृत्ति की आयु बढ़ा दी जाएगी तो जज लंबे समय तक काम करने के इच्छुक हैं। इसी 18 नवंबर को भारत के 47वें मुख्य न्यायाधीश का पदभार ग्रहण करने वाले चीफ जस्टिस बोबडे ने गुरुवार को अटर्नी जनरल केके वेणुगोपाल के सुझाव पर ऐसा कहा। हालांकि खुद वेणुगोपाल का कहना है कि ऐसा उन्होंने बार एसोसिएशन के सदस्य होने के नाते कह रहे हैं, नाकि देश के सर्वोच्च कानून अधिकारी के तौर पर कह रहे हैं। उल्लेखनीय है कि सुप्रीम कोर्ट के जजों के रिटायर होने की उम्र 65 साल है जबकि हाई कोर्ट के जज 62 साल के होने पर सेवानिवृत्त होते हैं।

सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन (एससीबीए) ने सीजेआइ के सम्मान में कार्यक्रम का आयोजन किया। इस समारोह को संबोधित करते हुए वेणुगोपाल ने कहा कि 70 और 80 साल से अधिक के वकील अदालतों में पूरे जोश-ओ-खरोश से जिरह करते हैं। इसलिए जजों की सेवानिवृत्ति की आयु सुप्रीम कोर्ट के लिए 70 साल तक की जा सकती है, जबकि हाई कोर्ट में उनकी सेवानिवृत्ति की आयु 68 वर्ष होनी चाहिए। बार के सदस्यों को संबोधित करते हुए चीफ जस्टिस बोबडे ने कहा कि आप अपने मुवक्किलों को बताएं कि वह अपना काम जारी रखना चाहते हैं। जस्टिस बोबडे ने अपनी चिंता जताते हुए कहा कि हमारी न्यायापालिका और बार दोनों ही स्वतंत्र हैं। हर मौके पर हम यह पूरे गर्व के साथ कह सकते हैं कि भूत और भविष्य में न्यायापालिका ने अर्थपूर्ण तरीके से दायित्वों का निर्वाह किया है। इसके साथ ही चीफ जस्टिस बोबडे ने न्यायपालिका के लिए चिंता के विषय उठाते हुए कहा कि लंबित मामले बढ़े हैं। आधारभूत ढांचे और रिक्तियों के मुद्दे हैं। इन्हें मिलजुलकर दुरुस्त करने की जरूरत है।

वहीं वेणुगोपाल ने अपने संबोधन में दलील दी कि देश के मुख्य न्यायाधीश का कम से कम तीन साल का तय कार्यकाल होना चाहिए। ताकि उनके नेतृत्व में शुरू किए गए सुधारवादी फैसलों को उनके ही कार्यकाल में अमल में लाया जा सके। एससीबीए अध्यक्ष और वेणुगोपाल दोनों ने ही वकीलों के और चैंबर बनाए जाने की मांग को पूरा करने और कोर्ट परिसर में और अधिक गलियारे बनवाने पर बल दिया जाएगा।

विदेश मंत्रालय ने पाक से फिर की दोनों भारतीयों को लौटाने की मांग

▶ विदेश मंत्रालय ने जताई उम्मीद, नहीं किया जाएगा दुष्प्रचार के लिए इस्तेमाल

नई दिल्ली, एजेंसियां : अनजाने में सीमा पार करके 2016-17 में पाकिस्तान चले गए दो भारतीय नागरिकों की गिरफ्तारी पर विदेश मंत्रालय ने गुरुवार को आश्चर्य व्यक्त करते हुए दोनों को काउंसलर एक्सेस देने और उन्हें वापस भेजने की मांग दोहराई।

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार ने बताया कि भारत ने कई महीनों पहले ही प्रशांत वैंदम और बारी लाल के अनजाने में सीमा पार करने की संभावना के बारे में पाकिस्तान को सूचित कर दिया था। लिहाजा पाकिस्तानी मीडिया में उनकी अचानक गिरफ्तारी की खबर से भारत को आश्चर्य हुआ है। उन्होंने कहा, 'हमें उम्मीद है कि इन दोनों भारतीय नागरिकों को पाकिस्तानी दुष्प्रचार के लिए इस्तेमाल या उसका पीड़ित नहीं बनाया जाएगा।'

रवीश कुमार ने बताया कि बारी लाल (मध्य प्रदेश निवासी) के सीमा पार करने की संभावना के बारे में भारत ने पाकिस्तान को पिछले साल दिसंबर में और प्रशांत वैंदम (तेलंगाना निवासी सॉफ्टवेयर इंजीनियर) के बारे में इस साल मई में सूचित किया था। उसके बाद से पाकिस्तान ने भारत के अनुरोध का कोई जवाब नहीं दिया है। उन्होंने कहा, 'जब यह मीडिया में आया तो हमने उसी दिन पाकिस्तान सरकार से संपर्क किया और उन्हें तत्काल काउंसलर एक्सेस दिए जाने का अनुरोध किया।' रवीश कुमार ने बताया कि ऐसे कई अन्य भारतीय भी हैं जो संभवतः अनजाने में सीमा पार करके पाकिस्तान चले गए हैं। जब भी ऐसे मामले विदेश मंत्रालय के संज्ञान में आते हैं तो पाकिस्तान से संपर्क किया जाता है।

बता दें कि पाकिस्तानी मीडिया ने इसी हफ्ते की शुरुआत में खबर दी थी कि पंजाब प्रांत के पूर्वी शहर बहावलपुर से दो भारतीयों को गिरफ्तार किया गया है। वे वहां बिना वैध दस्तावेजों के रह रहे थे।

करतारपुर कॉरिडोर के मद्देनजर पंजाब में पासपोर्ट सेवाओं का विस्तार

रवीश कुमार ने बताया कि करतारपुर कॉरिडोर खुलने के बाद यात्रा दस्तावेजों के लिए बढ़ते आवेदनों के मद्देनजर विदेश मंत्रालय ने पंजाब में पासपोर्ट सेवाओं का विस्तार किया है। उन्होंने कहा, 'पासपोर्ट सेवाओं को आसान बनाया गया है। पंजाब में अब तीन पासपोर्ट कार्यालय, पांच पासपोर्ट सेवा केंद्र और छह पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट सेवा केंद्र हैं। इनके अलावा डेरा बाबा नानक समेत कई नए पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट सेवा केंद्र खोले जा रहे हैं।' मालूम हो कि करतारपुर साहिब जाने के लिए पहचान पत्र के तौर पर पासपोर्ट अनिवार्य है।

वेतन घोटाले में लखनऊ के होमगार्ड कमांडेंट गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, लखनऊ : होमगार्ड विभाग में वेतन घोटाले की आंच आखिरकार राजधानी लखनऊ तक पहुंच गई। लखनऊ में होमगार्डों की फर्जी ड्यूटी लगाकर वेतन हड़पने का फर्जीवाड़ा सामने आने के बाद गोमतीनगर पुलिस ने जिला होमगार्ड कमांडेंट कृपा शंकर पांडेय को बुधवार देर रात गिरफ्तार कर लिया।

कूटरचित दस्तावेज से मस्टर रोल तैयार कर सरकारी धन का गबन करने के आरोप में जिला कमांडेंट को गिरफ्तार किया गया है। यह जालसाजी विभूतिखंड थाने में तैनात होमगार्डों के नाम पर भी हुई है। मामले में इंस्पेक्टर गुडंबा रीतेंद्र प्रताप सिंह ने गोमतीनगर थाने में जिला कमांडेंट होमगार्ड कार्यालय के अधिकारियों व कर्मचारियों के खिलाफ एफआइआर दर्ज कराई। आरोप है कि जुलाई और अगस्त 2019 में गुडंबा थाने में होमगार्डों की वास्तविक तैनाती के अपेक्षा तीन गुना से अधिक वेतन का भुगतान करा लिया।

जांच में पता चला कि अगस्त में गुडंबा थाने में कुल 23 होमगार्ड आवंटित किए गए थे। इनमें महज आठ ही ड्यूटी पर भेजे गए। इंस्पेक्टर गुडंबा ने उन्हीं आठ होमगार्ड के वेतन की रिपोर्ट बनाकर भेजी। बावजूद इसके जिला होमगार्ड कमांडेंट ने कुल 23 होमगार्ड के नाम पर भुगतान प्राप्त कर लिया। जुलाई और अगस्त में सिर्फ गुडंबा थाने में होमगार्डों की ड्यूटी में खेल कर चार लाख 99 हजार रुपये का गबन हुआ।

सैन्य काफिले को उड़ाने की आतंकी साजिश नाकाम

कश्मीर के जिला कुलगाम में जम्मू-श्रीनगर हाईवे पर आतंकियों की ओर से लगाई गई आइईडी का सुरक्षाबलों ने समय रहते पता लगाकर उसे निष्क्रिय कर दिया। पीआरओ डिफेंस

राज्य ब्यूरो, श्रीनगर

सुरक्षा बलों की सतर्कता से गुरुवार को दक्षिण कश्मीर में जम्मू-श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर सैन्य काफिले और नागरिक वाहनों को उड़ाने की बड़ी आतंकी साजिश नाकाम हो गई।

जानकारी के अनुसार, आतंकियों ने जम्मू-श्रीनगर हाईवे पर कुलगाम के अंतर्गत वनपोह में अल-स्टाप के पास एक आइईडी लगा रखी थी। जांच के दौरान इसका पता चलते आवाजाही रोक दी गई। बम निरोधक दस्ते को बुलाया गया। दस्ते ने सुरक्षित जगह पर ले जाकर आइईडी को निष्प्रभावी कर दिया।

बैग में रखा गया था विस्फोट : अधिकारियों ने बताया कि आइईडी को एक बैग में विस्फोटकों से भरे दो छोटे टीन के डिब्बे और बिजली के तारों से फिट किया गया था। आसपास रहने वाले लोगों और दुकानदारों से भी पूछताछ की गई है, लेकिन कोई भी आइईडी रखने वालों के बारे में जानकारी नहीं दे पाया है।

त्राल में दुकानदारों को धमका रहा हिजबुल का ओजीडब्ल्यू गिरफ्तार

राज्य ब्यूरो, श्रीनगर

दक्षिण कश्मीर के त्राल में लोगों को डरा-धमका कारोबार बंद रखने के लिए मजबूर कर रहे तत्वों के खिलाफ अभियान छेड़ते हुए पुलिस ने हिजबुल मुजाहिदीन के ओवरग्राउंड वर्कर को पकड़ लिया है। भारी मात्रा में धमकी भरे पोस्टर, आतंकी संगठन के लैटरहेड व अन्य आपत्तिजनक सामग्री बरामद की है।

पुलिस प्रवक्ता के अनुसार, आरोपित आसिफ अहमद बट लारू जगीर पर त्राल पुलिस स्टेशन में लोगों के साथ मारपीट, धमकियां देने, दंगा भड़काने, आगजनी के कई मामले दर्ज हैं। आसिफ त्राल और आसपास के इलाकों में लोगों को हड़ताल करने के लिए उकसा रहा था। वह दुकानें खोलने वालों के साथ मारपीट करता था। उसने कुछ जगहों पर खुली दुकानों को आग लगाने की साजिश की थी। पुलिस ने कई बार उसके ठिकानों पर दबिश दी, लेकिन वह हर बार बच निकलता था। सुबह पुलिस ने उसे दबोच लिया। उससे गत सप्ताह त्राल में एक दुकानदार की हत्या के मामले में पूछताछ होगी।

गौरतलब है कि जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 समाप्त होने के बाद से जम्मू-कश्मीर में आतंकवादियों को हौसले पस्त दिख रहे हैं। कुछ दिन की पाबंदियों के बाद हालात लगातार सामान्य हो रहे हैं। ऐसे में आतंकवादी संगठन लगातार दुकानदारों को डरा रहे हैं ताकि बाजार बंद रहे।

पुंछ में पाक गोलाबारी में बीएसएफ का जवान घायल

जासं, पुंछ : पाकिस्तानी सेना ने गुरुवार को कृष्णा घाटी सेक्टर में भारतीय चौकियों और रिहायशी क्षेत्रों को निशाना बनाकर भारी गोलाबारी की है। इसमें सीमा सुरक्षा बल का एक जवान घायल हो गया। जवान की पहचान 168 बटालियन के संजय कुमार के रूप में हुई है। डॉक्टरों के मुताबिक उसकी हालत में सुधार है। भारतीय सेना की जवाबी कार्रवाई में सीमा पार काफी नुकसान हुआ है।

चिंता

हवाला कारोबार और आतंकी गतिविधियों के कारण लगी रोक, भारी कर्ज में फंसे जम्मू कश्मीर के व्यापारी, कारोबार चौपट

क्रॉस एलओसी ट्रेड बंद होने से गुलाम कश्मीर में लाखों फंसे

राज्य ब्यूरो, श्रीनगर

तौसीफ जफर रोज सुबह नई उम्मीद लेकर घर से करीब 12 किलोमीटर दूर सलामाबाद जाते हैं और फिर मायूस होकर लौट आते हैं। जेहलम किनारे स्थित सलामाबाद क्रॉस एलओसी ट्रेड फैसिलटेशन सेंटर में अधिकारियों से गुलाम कश्मीर में फंसे पैसे निकालने का कोई रास्ता बताने को कहता है। अधिकारी सांत्वना देते हैं कि हौसला रखो, जल्द ही ट्रकों की आवाजाही शुरू हो जाएगी। रोज यही आश्वासन लेकर घर लौट आता है। वह अकेला नहीं है उस जैसे करीब 180 व्यापारी हैं, जिनका लाखों रुपया गुलाम कश्मीर के व्यापारियों पर है।

उड़ी निवासी तौसीफ जफर का कहना है कि जब क्रास एलओसी ट्रेड शुरू हुआ तो बताया गया कि यह हम लोगों की तकदीर बदल देगा, लेकिन आज हम लोग सड़क पर हैं। 70 लाख का माल अप्रैल की शुरुआत में भेजा था बदले में चकोटी मुजफ्फराबाद के व्यापारियों को मुझे सामान भेजना था। वह सामान भेजते उससे पहले ही 18 अप्रैल को क्रॉस एलओसी व्यापार पर रोक लगा दी गई। छह ट्रक माल यहां रखा था जिसे 19 अप्रैल को भेजना था। वह कहते हैं कि एक बार किसी तरह से पैसा वापस आए। उसके बाद इससे तौबा ही कर लूंगा।

श्रीनगर के जहूर अहमद बताते हैं कि कि अप्रैल के अंत में 30 लाख के मसाले खरीदे थे, जो गुलाम कश्मीर भेजने थे और बदले में मिस्वाक की दातुन मंगानी थी। मई में पाक रमजान में मिसवाक की यहां खूब खपत होती है, लेकिन अप्रैल के दूसरे पखवाड़े में यह व्यापार बंद हो गया और मैं कर्ज में दब गया।

केंद्र ने हमारी सुनी नहीं : सलामाबाद-चकोटी क्रास एलओसी ट्रेडर्स एसोसिएशन के चेयरमैन हिलाल तुर्की ने कहा कि हम तो शुरू से केंद्र सरकार से कहते थे कि वह इस व्यापार को हवाला और आतंकवादियों की चंगुल से आजाद रखने के लिए ट्रेड फैसिलटेशन सेंटर पर ट्रक स्कैनर उपलब्ध कराए। सभी व्यापारियों की स्क्रीनिंग हो। यह व्यापार बार्डर ट्रेड जिसमें सामान के बदल-सामान का आदान-प्रदान होता है, बंद करने और नकद लेन-देन की व्यवस्था के लिए आग्रह कर रहे थे। केंद्र ने हमारी यह मांग पूरी नहीं की।

300 मजदूर बेरोजगार हो गए : सलामाबाद का बाजार दिनभर सूना रहता है। दो सौ ट्रक चालक बेकार हैं। अब श्रीनगर, बारामुला व कस्बों में काम तलाश रहे हैं। ट्रेड फैसिलटेशनसेंटर में 300 मजदूर काम करते थे, जो बेकार हैं। इनमें से कई कश्मीर से बाहर रोजी रोटी कमाने चले गए हैं। लोगों का कहना है कि दोनों देशों की तनातनी से मजदूरों को ही नुकसान उठाना पड़ रहा है। उन्होंने दोनों देशों की सरकार से इस दिशा में पहल करने की अपील है। उनका कहना है कि इससे दोनों देशों के बीच भाईचार भी बढ़ेगा।

प्रशासन तक बात पहुंचा दी : सलामाबाद ट्रेड फैसिलटेशन सेंटर के कस्टोडियन रियाज अहमद मलिक ने कहा कि व्यापार कब शुरू होगा यह केंद्र सरकार तय करेगी। स्थानीय व्यापारियों की पीड़ा प्रशासन तक पहुंचा दी है।

18 अप्रैल 2018 को बंद हुआ व्यापार

गत मार्च में क्रास एलओसी ट्रेड को कुछ दिन स्थगित रखने के बाद बहाल किया गया, लेकिन 18 अप्रैल को गृहमंत्रालय ने अधिसूचना जारी कर इसे अगले आदेश तक बंद करने का निर्देश दिया।

वर्ष 2008 में शुरू हुआ था क्रास एलओसी ट्रेड

भारत-पाकिस्तान के बीच एक समझौते के तहत अक्टूबर 2008 में जम्मू कश्मीर और गुलाम कश्मीर के बीच ड्यूटी फ्री क्रास एलओसी ट्रेड की अनुमति दी गई थी। इसमें सिर्फ जम्मू कश्मीर और गुलाम कश्मीर के व्यापारी ही हिस्सा ले सकते थे। दोनों तरफ से 21 वस्तुओं का ही आयात-निर्यात हो सकता था। यह पूरी तरह से बार्टर ट्रेड था। कश्मीर के व्यापारी सलामाबाद के रास्ते अमन कमान सेतु के पार गुलाम कश्मीर की राजधानी मुजफ्फराबाद के लिए माल भेजते थे और मंगाते थे। जम्मू के व्यापारी पुंछ में चक्कां दा बाग के रास्ते रावलकोट माल भेजते थे। यह व्यापार सप्ताह में चार दिन होता था।

उप्र के पीएफ घोटाले में दो और सीए सहित पांच से पूछताछ

राज्य ब्यूरो, लखनऊ

उप्र में बिजलीकर्मियों के भविष्य निधि घोटाले में दिल्ली के दो और चार्टर्ड अकाउंटेंट (सीए) से लंबी पूछताछ की गई है। आर्थिक अपराध अनुसंधान शाखा (ईओडब्ल्यू) ने ब्रोकर फर्मों के जरिये हुए करोड़ों के कमीशन का लखनऊ कनेक्शन भी खोज निकाला है।

सूत्रों का कहना है कि लखनऊ के महानगर क्षेत्र निवासी ब्रोकर फर्म संचालक अश्वनी भसीन व राहुल भसीन सहित तीन फर्म संचालकों से लंबी पूछताछ की गई। अश्वनी भसीन व राहुल भसीन की चार ब्रोकर फर्में, जिनमें दो फर्में लखनऊ व दो फर्में दिल्ली के पतों पर रजिस्टर्ड हैं। दोनों को कमीशन के रूप में करीब सवा करोड़ रुपये का भुगतान हुआ था। ईओडब्ल्यू की जांच में यह भी सामने आया है कि श्रीन कंसलटेंट व एरीज एंड कंपनी नाम से रजिस्टर्ड फर्मों के जरिये भी निजी कंपनी दीवान हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (डीएचएफएल) में निवेश कराया गया था। उल्लेखनीय है कि ईओडब्ल्यू ने मंगलवार को पानीपत की फर्जी ब्रोकर फर्म के संचालक से लंबी पूछताछ की थी। अब तक की जांच में ब्रोकर फर्मों से जुड़े रहे दिल्ली के कई सीए की भूमिका भी सामने आई है। दिल्ली के चार सीए से बुधवार को पूछताछ के बाद ईओडब्ल्यू ने गुरुवार को दो अन्य सीए से भी लंबी पूछताछ की। फर्जी फर्मों के खातों से किए गए ट्रांजेक्शन की पड़ताल में सामने आये कई बैंक खातों के बारे में भी सिलसिलेवार छानबीन की जा रही है।

सूत्रों का कहना है कि छानबीन में दलाल फर्मों व पावर कारपोरेशन के अधिकारियों के बीच सीधे संबंध भी सामने आए हैं। ईओडब्ल्यू इसके साक्ष्य जुटाने का प्रयास कर रही है। 4122.70 करोड़ के भविष्य निधि घोटाले की जांच शासन ने ईओडब्ल्यू को सौंपी है। ईओडब्ल्यू अब तक आरोपित तत्कालीन निदेशक (वित्त) सुधांशु द्विवेदी, सचिव ट्रस्ट पीके गुप्ता, एमडी एपी मिश्र, पीके गुप्ता के बेटे अभिनव व फर्जी ब्रोकर फर्म संचालक आशीष चौधरी को गिरफ्तार कर चुकी है।